

अपील पत्रावली संख्या 181/13 सुखराम/प्रहलाद वगै०

जॉच किये बिना ही आदेश पारित किया है। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना

रिपोण्डेण्ट के अधिवक्ता ने बहस में बताया कि रेस्पों 2 लगायत 5 ने अपने द्वारा काश्त करना न्यायालय में स्वीकार किया है। अतः उनके विरुद्ध प्रार्थनापत्र पेश किया है वह सही है। अपीलार्थी रिपोण्डेण्ट के आधार पर अपनी खातेदारी होने का कथन किया है उस बारे में यह न्यायालय विचार कर सकता है। उन्हें पहले अपने नाम खातेदारी की घोषणा करानी चाहिये। अपीलार्थी को कानूनन संख्या 2 लगायत 5 से भूमि काश्त कराने का अधिकार नहीं है। रेस्पों संख्या 1 खातेदार है। अतः रिपोण्डेण्ट द्वारा प्रार्थनापत्र पेश किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बिलकुल सही है। अपीलार्थी द्वारा रिपोण्डेण्ट फर्जी है यदि ऐसे दस्तावेज थे तो उन्हें अब तक खातेदारी की घोषणा करानी चाहिये थी।

रिपोण्डेण्ट अधिवक्ता की बहस के जवाब में अपीलार्थी अधिवक्ता ने बताया कि यदि उक्त प्रार्थनापत्र रिपोण्डेण्ट अनुसार रेस्पों संख्या 1 को कब्जा सुपुर्द कर दिया गया तो अपीलार्थी को अपूर्ण्य क्षति होगी। कब्जा यदि बतौर अतिक्रमी भी माना जावे तो भी उन्हें सुना जाना चाहिये था।

दोनों विद्वान अभिभाषकों की बहस को गौर किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन रिपोण्डेण्टस 2 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में भी जवाब पेश किया था जिसमें अपीलार्थी एवं संख्या 6 की भूमि होना बताया था तथा उनकी ओर से काश्त करना था। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई जॉच नहीं की गई। प्रार्थी/रेस्पों संख्या 1 की ओर से कोई गवाह पेश नहीं हुए। रिपोण्डेण्ट के भी बयान नहीं हुए। केवल रेस्पों संख्या 1 के प्रार्थनापत्र एवं जवाब उल जवाब पर विचार ही निर्णय पारित किया गया। विवादित भूमि का सह खातेदार दुर्गा पुत्र नेतराम रेगर था उसे भी कब्जा नुकदमा नहीं बनाया। रेस्पों संख्या 1 की खातेदारी दुर्गा पुत्र नेतराम के साथ संयुक्त रूप से है। उक्त कब्जा खसरा नम्बर 635,636,637 में दुर्गा पुत्र नेतराम के कब्जे में कौनसी भूमि है तथा अपीलार्थी अथवा संख्या 1 के कब्जे में कौनसी भूमि है तय किये बिना बेदखली के आदेश की पालना किया जाना गलत होगा। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बारे में कोई विचार नहीं किया है। रेस्पों 2 लगायत 5 ने अपीलार्थी एवं रेस्पों संख्या 6 की ओर से काश्त करना बताया था तो वे आवश्यक पक्षकार होना जरूरी हो चुका था। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में जॉच की जानी चाहिये थी अथवा उन्हें कब्जा बनाया जाना चाहिये था। अपीलार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के प्रार्थनापत्र के साथ अपील पेश की है। उनके द्वारा अपील में जो ग्राउण्ड बताये हैं उससे वे आवश्यक पक्षकार होना साबित है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 25/10/13 अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी के साथ भूमि के सह खातेदार दुर्गा पुत्र नेतराम रेगर को पक्षकार बनाते हुए रिपोण्डेण्ट में पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार, गंगापुरसिटी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 07/07/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर